जनगर्जन

वर्ष 24 अंक 6 मासिक नई दिल्ली फरवरी 2010 विक्रमी संवत्-2066 प्रधान संपादक: देवब्रत बिश्वास, वार्षिक-शुल्क: 60रुपये

मूल्यवृद्धि के खिलाफ वामपंथी दलों की रैली सफल बनायें

देवब्रत बिश्वास, महासचिव, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक

चार वाम दलों माकपा, भाकपा, फारवर्ड ब्लॉक और आरएसपी ने मूल्य वृद्धि के खिलाफ और खाद्य सुरक्षा के लिये 12 मार्च 2010 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली का आयोजित करने का निर्णय लिया है। वामदलों ने रैली को व्यापक रूप से सफल बनाने के लिये अपनी तैयारियाँ पहले ही शुरू कर दी हैं। यह रैली उन भाड़े के लेखकों एवं उनके चट्टे-बट्टे के लिये करारा जवाब होगा जो लगातार वाम दलों पर चोट किया करते हैं। यह रैली सभी के लिये रोजगार की आवाज को बुलंद करेगा और बहु प्रचारित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (नरेगा) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में व्याप्त गड़बड़ियों को समाप्त करने पर जोर डालेगा। रैली नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों व भूमण्डलीकरण के कारण किसानों एवं मेहनत कशों की दयनीय दशा एवं संकटों को भी उजागर करेगा।

मूल्यवृद्धि के खिलाफ-

केन्द्र सरकार सिर्फ मूकदर्शक बनकर रह गयी है जबकि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें दिन प्रतिदिन बेतहाशा बढ़ रही है। चावल, खाद्य तेल, अनाजों, सब्जियों, फलों और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें आमसान छू रही हैं तब केन्द्रीय सरकार इसके लिये सीधे राज्य सरकारों को आरोपित करते हुये रोज-बरोज विरोधाभाषी वक्तव्यों को जारी कर रही हैं। विभिन्न प्रकार के दालें एवं चीनी गरीब आदमी के पहुँच से बाहर हो चुकी है। देश के विभिन्न भागों में चीनी की कीमतें 50 रुपये प्रतिकिलो तक अप्रत्याशित रूप से बढ़ चुकी है। दाल की कीमत भी 80 रुपये प्रति किलो से 110 रुपये प्रतिकिलो तक पहुँच गयी है। बल्कि यह कहना बेहतर होगा कि खाद्य तेल तो मध्यम वर्ग के पहुँच के बाहर हो गया है। बाजारों में मौसमी सब्जियों की कीमतों में आग लगी है और काफी ऊँची कीमतों में बेची जा रही है। आखिर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में यह अप्रत्याशित वृद्धि क्यों हुई ?क्या देश में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा या फसलों की महामारी हुई है, जिसने हमारी कृषि उपज को ध्वंस कर दिया है ?जवाब नकारात्मक है। फिर यह मूल्यवृद्धि क्यों ?जवाब सीधा सा है कि यह केन्द्रीय सरकार की खाद्य नीति जिसने बड़े पैमाने पर वायदा कारोबार एवं जमाखोरी की वजह से है।

खुदरा व्यापार में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और कार्पोरेट व्यापारिक घरानों के प्रवेश ने संविदा खेती के दरवाजे खोल दिये हैं और इसने फसलों की कटनी के पूर्व ही कृषि उत्पाद की कीमतों को निर्धारित करने का अवसर भी प्रदान कर दिया है। नीजि व्यापारी किसानों से उनके कृषि उत्पाद को खेतों से सीधे उनसे खरीदकर रहे हैं और उसे अपने गोदामों, माल गोदामों में जमा कर रहे हैं। फिर वे धीरे-धीरे अपनी मनमानी कीमत निर्धारित कर उन मालों को बाहर निकालते है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे स्त्रोत से खरीदना भी चाहता है तो यह संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ये वस्तुएं उन कारपोरेट घरानों के माल गोदामों में बंद हो चुकी होती है। यहाँ तक कि यदि सरकार भी उसे खरीदना चाहती है तो उसे भी इन व्यापारियों को निर्धारित ऊँची कीमत पर खरीदना पड़ता है। यह एक कठिन कार्य है। सरकारी एजेन्सियां व राज्य व्यापारिक निगम भी इन कारपोरेट घरानों की प्रतिस्पर्द्धा में टिक नहीं पाती है। अतएव वे अपने को बाजार से वापस हो जाती है और संचय की प्रक्रिया से भी।

सरकार इस परिस्थिति का आकलन करने में विफल रही है और इस परिस्थिति से निबटने के लिये उसने बड़ी मात्रा में स्टाक जमा करने के लिये कुछ भी नहीं किया है। यह दुर्भाग्य है कि देश ने सफलता पूर्वक हरित क्रांति का संचालन किया था लेकिन अब वही चावल और गेहूँ सहित आवश्यक वस्तुओं का आयात कर रही हैं। सरकार खाद्य स्फीति के आंकड़ें दर्शाने में व्यस्त है और इस समस्या को केन्द्र के पाले से राज्य सरकारों के पाले में फेंकने के लिये प्रयासरत है। लेकिन तथ्य यह है कि की मुद्रास्फीति का आंकड़ा जो भी हो उससे लोगों का कोई लेना-देना नहीं। उन्हें सिर्फ कम कीमत पर खाद्य पदार्थ चाहिये। यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि केन्द्र सरकार ने बिना किसी तर्क और औचित्य के केन्द्र के पाले से खाद्य वस्तुओं की कीमतों के मुद्दे को बढ़ा दिया। कीमतें बढ़ने के बाद, राज्य सरकारों को इसे तुरंत दुरूस्त करने को कह दिया। राज्य सरकारें अपने खजाने से भारी सब्सिडी देने के कारण भारी दबाव में है और इस प्रकार के असहनीय बोझ को वहन करने में असमर्थ है।

यह भी एक विरोधाभास है कि इस अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि के बावजूद किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। इसका तात्पर्य है कि कारपोरेट

घरानें और बिचौलियें ही उपभोक्ताओं और किसानों, जो कि इसका उत्पादन कर रहे हैं, का शोषण कर रहे हैं। कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिये सरकार कोई कदम उठा नहीं उठा रही हैं और न ही किसानों को ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित डॉ. स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की सुझावों पर भी अमल किया। किसानों के उत्पाद को खरीद करने में विफल सरकारी एजेंसियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। सरकार का इस विफलता का लाभ आयातकों को मिल रहा है। खाद्य पदार्थों के निर्यात बन्द कर देने चाहिये। समय की मांग के अनुसार वितरण प्रणाली को पुनर्जीवित करके आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किया जाना चाहिये।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम सुनिश्चित हो

प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बचे हुये ढाँचे को नष्ट करने का एक अन्य हथियार बन गया है। प्रस्तावित कानून में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सिर्फ बीपीएल वर्ग के लोगों के लिये ही सिफारिश है। जिसके तहत उन्हें 3 रुपये प्रति किलो की दर से 25 किलो चावल या गेहूँ ही मिलेगा। जबकि कई राज्य सरकारें पहले से ही 2 रुपये प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल या गेहूँ बीपीएल वर्ग को वितरित कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भोजन की मात्रा कम होगी और उसके दामों में वृद्धि होगी। बिना किसी शिकायत के कई राज्यों में बीपीएल और एपीएल वर्ग के अंतर कर पाना बड़ा कठीन है। एक रिपोर्ट यह भी है कि योजना आयोग और अन्य सरकारी एजेन्सियों में गरीबी रेखा के मानदंड को परिभाषित करने के विचारों में अंतर है। यह भी सत्य है कि नागालैण्ड से महाराष्ट्र तक और केरला से कश्मीर तक राज्यों में खाद्य की आवश्यकता में भिन्नता है। अत: भारत सरकार को चाहिये कि इस कानून को ग्रहण करने से पूर्व एक व्यापक चर्चा करनी चाहिये। लोगों को वर्गीकृत करने के बजाय, सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाये और खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिये बाजार में हस्तक्षेप करके सभी योग्य उपायों को अपनाये।

रोजगार के लिए

संप्रग-1 सरकार में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (नरेगा) प्रमुख कार्यक्रम था। सरकार वामदलों के दबाव में आकर इस योजना को लागू करने के लिये बाध्य हो पाई। लेकिन विभिन्न राज्यों से मिल रही सूचनाओं दर्शाति है कि नरेगा के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर विसंगतियाँ है और धोखेबाजी हो रही है। जॉब कार्ड जारी करने, कार्य वितरण, न्यूनतम मजदूरी, कार्य की प्रकृति, लिंग समानता आदि में कई तरह की गड़बड़ियां हो रही है एवं बेरोजगारों और सरकार को नौकरशाह और ठेकेदार धोखा दे रहे हैं। कई अध्ययनों और सार्वजनिक लेखा परिक्षणों से पता चलता है कि कई राज्यों में क्षेत्रिय नेताओं और ठेकेदारों के साथ मिलकर नौकरशाहों ने नरेगा को पैसा कमाने का यंत्र बना लिया है। इस शोषण के खिलाफ संघर्ष करने वालों की राजनैतिक हत्यायें हो रही है। सरकार नरेगा के क्रियान्वयन के लिये तथा सार्वजनिक लेखा परिक्षणों को बढ़ाने के लिये सर्वव्यापि निगरानी रखे। सरकार इस योजना के विस्तार के लिये उचित कदम उठाये और इसमें कार्य के दिनों को भी बढ़ाये। कार्य दिवसों के बढ़ोतरी करने के साथ-साथ सरकार देश के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने के लिये उपायों और योजनाओं की भी तलाश करे। इसके अलावा वैश्विक मंदी के समाप्त हो रहे रोजगारों के कारण लाखों कामगारों की बेरोजगारी के संबंध में भी सरकार को सोचना चाहिये। सरकार से लाभ उठाने और खैरात पैकेज के लिये कई कंपनियों में छंटनी से तालाबंदी हो रही है। सरकार ने कारपोरेटरों और कंपनियों के लिये कई राहत पैकेजों की घोषणा कर दी, लेकिन कंपनी से निकाले गये मजदूरों के पुनर्स्थापन या लाखों बेरोजगारों के लिये सरकार ने कई योजना नहीं बनाई। सकार को श्रमिकों के लिये विशेष राहत पैकेज देने चाहिये और उत्पादन में वृद्धि के लिये राहत पैकेजों को व्यापक सारणीवद्ध किया जाना चाहिये।

वाम विरासत को प्राथमिकता

15वीं लोकसभा चुनाव के पश्चात्, वामदलों पर विभिन्न स्तरों पर कई हमलें किये जा रहे हैं। वाम छवि को धूमिल करने के लिये धार्मिक कट्टरपंथी ताकतें, प्रतिक्रियावादी समूह और चरम वामपंथी ये सभी एकजुट होकर एक ही स्वर में बोल रहे हैं। साम्राज्यवादी ताकतें और उनके भारतीय एजेंट इन्हें पैसे और अन्य सुविधायें मुहैया कराकर वाम विरोधी अभियान चला रहे हैं। बड़ी ताकत के साथ पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में वामपंथी सरकारों को बदनाम करने किया जा रहा है। अत: वामदलों के सामने एक अपने साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष, पूँजीवादी, साम्प्रदायवादी, धार्मिक कट्टरवाद, चरम वामपंथी और शोषण के खिलाफ संघर्ष को और तेज करके वाम विरासत को ऊँचा उठाना होगा। इस परिस्थिति में 12 मार्च 2010 की प्रस्तावित सामूहिक रैली का अपना अलग ही महत्व है। सिर्फ पार्टियों के लिये ही नहीं बल्कि जन-संगठनों को भी इस रैली को सफल बनाने के लिये सभी प्रयास करने चाहिये।

पिछले अंक का शेषः.....

किसानी घोषणा पत्र

डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा

नहीं, किसानी घाटे का सौदा बनी नहीं है, उसको घाटे का सौदा बना दिया गया है। चाहे किसान हो या खेतिहर मजदूर, दोनों की हालत अखिर में इसी बात से तय होगी कि किसानी के कामकाज, जिसमें वे दोनों ही जुटे हैं, की हकदारी कितनी है ?किसानी की हकदारी के मामले में धोखा मोटा मोटी तीन तरह से हुआ है। पहला धोखा तो मेहनत के मोल के उसूलों में ही है। संगठित क्षेत्र मेमं मेहनत का मोल तय करने के लिये उसूल है कि काम करने वाले को इतना तो मिलना ही चाहिये जिससे उसके पूरे परिवार का अच्छी तरह भरण-पोषण हो सके, आड़े वक्त के लिये कुछ बच सके और सामाजिक प्राणी के रूप में भले से जी सके। परन्तु असंगठित क्षेत्र के लिये, जिसमें किसान, मजदूर और दस्तकार भी शामिल है, यह उसूल लागू नहीं है। उनकी मजदूरी तय करने में सरकार अधिक से अधिक यह मानती है कि परिवार में दो कमाने वाले अपनी मजदूरी से परिवार का काम चला सकें और वह भी मात्र गरीबी की रेखा तक पहुँच जाने की।

किसानी के साथ दूसरा धोखा किसानी को अकुशल कामकाज का दर्जा देकर किया गया है। दुनिया में भला किसानी से अधिक महत्वपूर्ण होने की बात तो दूर, उससे ज्यादा कुशल काम कौन हो सकता है ?यह बात अलग है कि किसानी में लगा आदमी अपना कौशल कॉलिज में नहीं, खेत पर अर्जित करता हैं। इसी धोखे के चलते, इन्हीं उसूलों की छाया में किसानी की हकदारी इतनी दबती गई कि आज वह चपरासी से भी पाँच सीढ़ी नीचे है।

धोखाधड़ी की तीसरी बात किसानी के काम कम नाप-तोल में हुई है। किसानी कोई दफ्तरी या करखनियां काम तो है नहीं जो मिनट दर मिनट घड़ी लगा कर नाप लो। ऐसे ही बेतुके सरकारी हिसाब में ढाई एकड़ वाले साधारण किसान का खरीफ और रबी दोनों फसलों में कुल जमा पूरे साल में 147 दिन का काम बैठता है। सो उन हिसाबियों की नजरों में साल में बाकी 218 दिन किसान ठलुआ रहता है। खेती में मेहनत मजदूरी के इस एक मद का अगर सही हिसाब लगाया जाये तो देश में सबसे बड़ी चोरी उजागर हो जायेगी। एक हिसाब के मुताबिक किसानी में लगे लोगों से एक साल में डेढ़ साल करोड़ रुपये की लूट हो जाती है। उस पर तुर्रा यह कि यहाँ गांव और गरीब पर सरकार कोई कर नहीं लगाती है। ऐसे फरेबी टैक्स के चलते भला किसान-मजदूर की कमर टूटने से कैसे बचती ?

इसे बिडम्बना कहें या राष्ट्रीय जीवन में बेईमानी की हद कि किसी भी राजनैतिक दल ने, या किसी भी प्रगतिशील कहलाने वाले बुद्धिजीवियों की जमात ने भी किसान और मजदूर के साथ इस धोखा-धड़ी और अन्याय की ओर जिक्र तक नहीं किया। समाजवाद के लिये मौके बेमौके उठती हुलास के दौरों में भी देश में आमदनी, वेतन और मजदूरी के लिये राष्ट्रीय नीति तय करने की बातें तो बहुत बार उठीं, परन्तु उसका संदर्भ सदा बहुत करके संगठित क्षेत्र तक ही सीमित बना रहा। ऐसा लगता है कि उनकी नजरों में गाँव के किसान - मजदूर - कारीगरों का मानों कहीं कोई वजूद ही नहीं है। ऐसे में अब हम यह सवाल उठाना चाहेंगे कि संविधान में किसी भी तरह के भेदभाव की मनाही के बावजूद जिन्दगी के लिये सबसे जरूरी काम में लगे सबसे सरल और भोले मेहनतकश की हकदारी तय करने के उसूलों में यह भेदभाव कैसा ?संसद, विधान सभायें और न्यायालय इस अहम मुद्दे पर चुप क्यों ?इसका एक ही जवाब है: किसानी के साथ इस धोखा-धड़ी और लूट में बाकी सका अपना निजी स्वार्थ अटका है। ये सभी सवाल को उठाते है ही वर्तमान व्यवस्था की अन्यायी स्थिति और उपनिवेशवादी जड़ें उजागर हो जायेंगी। हकदारी का असली सवाल पूरी अन्यायी व्यवस्था जड़ से हिल जायेगी। इसीलिये उस चुप्पी की साजिश में वे सब शामिल है।

संकल्प

हम भारत के किसान-मजदूर यह मानते हैं कि हमारे कृषि-प्रधान देश में विकास, खास तौर से उद्योगों के लिये शुरूआती पूँजी खेती-किसानी से ही निकाली जा सकती थी। परन्तु हमें खेद है कि इसके लिये सीधे सच्चे रास्ते की बजाय धोखाधड़ी और बेईमानी का रास्ता अपनाया गया। हमारी मेहनत की हकदारी में बिना हमारे जाने समझे आजादी के पहले से चली आ रही भारी कटौती खत्म होने की बजाय, बढ़ती गई। यही नहीं, उस शोषण को सथायी और जायज ठहराने की गरज से उपनिवेशवादी दौर से शुरू किये गये आधुनिक-संगठन और परम्परागत क्षेत्रों में काम करने वालों की हकदारी तय करने के लिये स्थापित भेदभाव भरे दो अलग उसूलों को आजादी के बाद भी वैसा ही लागू रखा गया जिसके चलते गैर-बराबरी तेजी से बढ़ती गई। अफसोस है कि इस अन्यायी और संविधान-विरोधी व्यवस्था पर हमारे राजनेताओं और बुद्धिजीवियों ने अपने दलगत और निजी स्वार्थों के कारण चुप्पी साधे रखी है। हम सभी न्यायप्रिय, विवेकी और प्रगतिशील नागरिकों का आवाहन करते हैं कि वे इस अन्यायी व्यवस्था की भर्तस्ना करें और उसे अमान्य करें। हम यह घोषणा करते हैं कि हम शहरी संगठित (वारिस) और ग्रामीण-असंगठित (बेदखल) क्षेत्रों के बीच बराबरी का रिश्ता कायम करेंगे और उन क्षेत्रों में अन्दरूनी गैर-बराबरी कम से कम करेंगे। कुदाल और कलम की समान प्रतिष्ठा होगी। उनसे जिन्दगी बसर करने वाली की हकदारियाँ भी समान होंगी। विभिनन क्षेत्रों के सदस्यों के बीच आर्थिक रिश्तों को तय करने का प्रमुख आधार उनमें काम करने वालों की मेहनत के लिये हकदरी होगा। हम यह भी घोषणा करते हैं कि उन उसूलों के तहत हमारे देश में किसानी की मेहनत का मोल संगठित क्षेत्र के कुशल कारीगर से कम नहीं होगा। पूरी व्यवस्था में शारीरिक या बौद्धिक हर तरह के काम करने वालों की मेहनत के मोल के बीच तीन गुणे से अधिक अंतर नहीं होगा। इस समीकरण में कठिन और जोखिम भरे कामों की हकदारी ज्यादा होगी।

गैर-हाजिर भूपतियों का खात्मा

मेहनतकश की हकदारी के बाद सबसे अहम सवाल धरती के उपयोग के अधिकार का है। धरती न तो संपत्ति है जिसे जैसा चाहे बाँटो-खूँटो और न वह पूँजी है जिससे कहीं भी बैठे-ठाले आमदनी की जुगाड़ कर लो। धरती जिन्दगी बसर करने के लिये इंसान का सहारा है। इस मामले में धरती मेहनत के आधार पर जिन्दगी बसर करने के लिये जुड़े बिना भी उस पर हकदारी की घोर अन्यायी व्यवस्था हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली। विडम्बना तो यह है कि आजादी के बाद भी, हर तरह के नारों और घोषणाओं के बावजूद, वह अन्याय और भी तेजी से बढ़ता गया। उधर, शहर और गाँव के बीच अन्यायी रिश्तों के पनपते जाने से खेती घाटे का सौदा होती गई। आज हालत यह है कि खेती उन्हीं को पुसाती है जिनके पास उसके अलावा कोई दूसरा धन्धा भी है। परन्तु इन दूसरे धन्धे वाले लोगों को खेती से ऊपज की बजाय जमीन के संपत्ति-मूल्य में अधिक दिलचस्पी है। इसीलिये दूसरे धन्धों में लगे और शहरों में रहकर धरती पर अपनी पुश्तैनी हकदारी बनाये रखने और हकदारी कायम करने की आज मुहिम सी चल रही है। ऊपर से लेकर नीचे तक शहर-बाजार में जिसको देखो उसके पास गाँव में जमीन है।

गैर-हाजिर भूपतियों की ऐसी भरमार पहले कभी नहीं थी। यही नहीं, ये लोग या तो खुद मंत्री से लेकर चपरासी तक के रूप में व्यवस्था में घुसे हुए हैं या व्यवस्था में उनकी पहुँच है। इसीलिये यह वर्ग भूमि सुधार के मामले में सबसे बड़े अवरोध साबित हुआ है। नये दौर में पूँजीवादी खेती की व्यवस्था की कायमी के लिये यही गुट वाहक शक्ति के रूप में भी उभरा है। इस व्यवस्था में खेती कहीं पुराने खिदमगारों से कराई जा रही है तो कहीं जमीन से बेदखल नये गुलाम फर्म हाउसों की अलकापुरी बनाने में जुटे हैं। बहरहाल, इस अन्यायी व्यवस्था का पूरा बोझ तो आखिर किसान-मजदूर को ही ढोना पड़ रहा है।

इस मामले में नजरियों का साफ होना और कुछ दो टूक बातें भी जरूरी है। हमारे मत में गैर-हाजिर भूपति की व्यवस्था हर तरह से अन्यायी है। वह गाँव, किसान और मजदूर के हितों पर कुठाराघात है। जो गाँव में रहकर खेती से जुड़ा नहीं है उसका उसके लाभ में किसी भी तरह की हकदारी होने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। चाहे फिर व सरकार हो या जमींदार-जागीरदार, पूँजीपति हो या धन्ना सेठ, भाई हो या जमाई। गँवई-गाँव में रहो बसो, सुख-दुख का भोग संग साथ में भोगो, धरती माता जो दे उससे मिल बाँट कर जिन्दगी बसर करो। 'गाँव की जमीन बेचकर शहर मेमं कोठियाँ बनें' या गाँव में खटे कोई और शहर में गुलर्छ़े कोई और उड़ायें', इसका कोई औचित्य नहीं हैं।

संकल्प

हम यह घोषणा करते हैं कि धरती संपत्ति नहीं है, वह जिन्दगी बसर करने का साधन है। इसलिये हम जमीन का चन्द हाथों में केन्द्रीकरण नहीं होने देंगे। गाँव के बाहर रह कर धरती पर कब्जा बनाये रखने का किसी के हक नहीं है। इसलिये हम यह घोषणा करते हैं कि गैर-हाजिर भूपतियों की फार्म हाउसों सहित पूरी जमीन गाँव के किसान-मजदूरों में बांट दी जायेगी। इसी तरह दूसरे धंधों में लगे लोगों का भाई हा या जमाई-जमीन पर या उसकी उपज में किसी तरह का हक नहीं होगा। पिता की जमीन पर अपने हाथ से खेती करने वाले वारिस का ही हक होगा। दूसरे वारिसों को उसको बेचने का अधिकार नहीं होगा।

गाँव की रिसन का खात्मा

किसानी की हकदारी में सेंध गाँव और गरीब की बदहाली का सबसे बड़ा कारण जरूर है परन्तु वह एकमात्र कारण नहीं है। उसके अलावा और भी अनेक करण है। गैर-हाजिर भूपतियों की बात अभी हम कर ही चुके हैं जो एक व्यापक दूर्व्यवस्था का अंग है। हमारे गाँवों के लोग वहां के प्राकृतिक संसाधनों (जमीन-जल-जंगल) का सीधा उपयोक कर अपनी जिन्दगी बसर करते हैं। इन संसाधनों से अंग्रेजों ने उनका अधिकार छीन लिया था जो आजादी के बाद भी वापिस नहीं मिला। इस अधिकार-हीनता के चलते उन संसाधनों के माध्यम से इंसान को मिलने वाली निसर्ग की देन यहाँ तक कि मेहनत से की गई खेती की पैदावार में निसर्ग का हिस्सा भी, सरकार हथिया लेती है। विज्ञान और तकनीक से होने वाली बढ़त भी बातार के मायाजाल में उसके हाथ से छीन जाती है। उसके बाद बची-खुची मेहनत की हकदारी में से भी हर तरह के बिचौलिये डंडी मार लेते हैं। इस तरह किसान-मजदूर के हाथ में मेहनत की दबी कटी हकदारी भी पूरी नहीं पहुँच पाती है।

- साभार - नीति मार्ग

23 जनवरी नेताजी जयन्ती 'देश प्रेम दिवस' के रूप में मनाया गया

23 जनवरी 2010, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का 114वां जन्मदिन अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ताओं और नेताजी के अनुयायियों द्वारा पूरे देश में मनाया गया। इस अवसर पर रैलियों, सार्वजनिक सभाओं, प्रदर्शनियों, सेमिनारों, बहस, कला और खेल की घटनाओं आदि का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता सेनानियों और आजाद हिन्द फौज के जवानों को सम्मानित करने के लिये विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मातृभूमि की आजादी में नेताजी के बलिदानों को याद करते हुये विद्यालयों और विश्वविद्यालयों प्रशासन ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया।

नेताजी के अनुयायियों का काफी समय से एक लंबित मांग रहा है कि 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस घोषित किया जाये। हालांकि 1996 में नेताजी के जन्मदिवस को 'देश प्रेम दिवस' घोषित करने के संदर्भ में सरकार को सिफारिश के लिये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक कमिटी का गठन

किया गया था जो युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने का सुनहरा अवसर था। लेकिन सत्ता में सभी सरकारों ने इसमें बहुत ही कम रूचि दिखाई। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक बहुत पहले से ही 'देश प्रेम दिवस' की घोषणा की मांग कर रहा है। इस मांग के समर्थन में पार्टी ने कई अभियान चलाये। लेकिन यह एक संतोषजनक बात है कि बिहार सरकार ने अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की मांग के अनुसार इस वर्ष से 23 जनवरी को 'देश प्रेम दिवस' घोषित कर दिया।

लेकिन केन्द्र सरकार लोगों द्वारा उत्साह के साथ देश प्रेम दिवस को मनाने के लिये अपनी अनिच्छा को ही जाहिर करती रही है। अत: देश में हजारों की संख्या जनता ने ही आगे कदम बढ़ाकर पूरे भारत वर्ष में लोगों के साथ देश प्रेम दिवस मनाया। इस मांग के साथ जनता ने सरकार से यह भी मांग किया कि नेताजी जाँच कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार किया जाये और नेताजी के ऐतिहासिक बलिदानों को विद्यालय और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये।

फारवर्ड ब्लॉक केन्द्र सरकार से मांग करती है कि नेताजी के जन्मदिवस 23 जनवरी को 'देश प्रेम दिवस' घोषित किया जाये और सभी शैक्षणिक संस्थानों में विशेष उत्सव का आयोजन किया जाए। यह सुझाव 1997 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नेताजी बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशन कमिटी ने भी सुझाया था। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक का विचार है कि यह घोषणा नव-युवकों में देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिये बहुत ही आवश्यक है। नेताजी का बलिदान और उनका इतिहास पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिये। इस मांग के समर्थन में फारवर्ड ब्लॉक राष्ट्रव्यापि आन्दोलन का आयोजन करेगा।

फारवर्ड ब्लॉक के केन्द्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी. देवराजन, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

दिल्ली :

दिल्ली राज्य में रंग-बिरंगी रैली का आयोजन आईटीओ के नजदीक स्थित भगत सिंह पार्क से लेकर दरियागंज में नेताजी सुभाष पार्क तक किया गया। सुभाष पार्क में एकत्रित जनसभा को पार्टी के राष्ट्रीय सचिव साथी जी. देवराजन ने संबोधित किया।

साथी जी. देवराजन ने जनसमुह को संबोधित करते हुये कहा कि कांग्रेस(आई) नीत संप्रग सरकार नेताजी के जन्म दिवस पर डीएवीपी के जरिये समाचारपत्रों या टी.वी. चैनलों पर किसी भी प्रकार विज्ञापन या प्रचार न देकर सरकार ने नेताजी के प्रति अपनी दुर्भावना का उद्गार किया है। जबकि यही सरकार छोटी सी पुलिया के उद्घाटन के लिये उसके प्रचार पर लाखों रुपये पानी की तरह बहा देती है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस(आई) हमेशा से ही नेताजी के बलिदान और इतिहास को दबाने की घृणित कोशिश करती रही है। उन्होंने मांग किया कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म दिवस 'देश प्रेम दिवस' घोषित किया जाना चाहिये और नेताजी के लापता होने से संबंधित मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना चाहिये। आज देश का नौजवान राष्ट्र विरोधी जनता के रास्तों पर जा रहा है, जिसके लिये सरकार को नौजवानों में देशभक्ति की भावना लाने के लिये विशेष कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिये तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के इतिहास और कार्यों को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिये।

सभा की अध्यक्ष साथी डी.एन.झा ने, अध्यक्ष दिल्ली राज्य कमिटी ने किया तथा उपस्थित जनसमूह को साथी धमेन्द्र कुमार वर्मा, महासचिव दिल्ली प्रदेश राज्य कमिटी, साथी पी.एन. द्वीवेदी, महासचिव टी.यू.सी.सी. दिल्ली प्रदेश राज्य कमिटी ने भी संबोधित किया।

झारखण्ड

राँची : अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की झारखण्ड राज्य इकाई की ओर से क्रान्तिवीर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 114वीं जन्म जयन्ती देश प्रेम दिवस के रूप में 23 जनवरी 2010 को राँची में मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय कचहरी के समीप नेताजी उद्यान में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा पर प्रांतीय महा सचिव साथी जनार्दन पाण्डेय, पार्टी के राँची जिला अध्यक्ष साथी सुमित बरियार, जिला मंत्री साथी उमाशंकर पाण्डेय आदि नेताओं ने माल्यार्पण किया। मौके पर साथी जनार्दन पाण्डेय ने झारखण्ड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को नेताजी के जन्म दिन 23 जनवरी को देशप्रेम दिवस के रूप में घोषित करने, 23 जनवरी को राजकीय अवकार घोषित करने एवं नर्सरी से स्नात्तकोत्तर तक के पाठ्यक्रमों में नेताजी के गौरवपूर्ण एवं देशभक्तिपूर्ण इतिहास को शामिल करने की मांग से संबंधित ज्ञापन समर्पित किया।

देवघर : अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की देवघर जिला इकाई की ओर से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का 114वीं जयन्ती देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा पर पार्टी के जिला अध्यक्ष साथी अरविन्द कुमार पाण्डेय, उपाध्यक्ष श्रीधर दूबे, कोषाध्यक्ष सुदामा पाण्डेय , मुरारी लाल बरनवाल, छात्र ब्लॉक के प्रदेश अध्यक्ष साथी सुशील कुमार पाण्डेय, नन्द किशोर प्रसाद वर्मा, ब्रज किशोर पंडित आदि नेताओं ने माल्यार्पण किया तथा साम्राज्यवादी शक्तियों को परास्त करने, जल-जंगल-जमीन के अधिकार की रक्षा करने, नेताजी के समाजवादी भारत के पुनर्निर्माण के सपने को साकार करने के लिये समझौता विहीन संग्राम को तेज करने का संकल्प ग्रहण किया।

गिरिडीह : पार्टी की जिला इकाई की ओर से गिरिडीह में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के 114वें जन्मदिन को देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर जिला महासचिव साथी सोमनाथ मुखर्जी, साथी संतु गोस्वामी, साथी शास्त्री कुमार वैद्य आदि ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

निरसा : पार्टी की अंचल इकाई की ओर से प्रखण्ड कार्यालय परिसर में नेताजी की प्रतिमा पर प्रांतीय अध्यक्ष साथी अपर्णा सेनगुप्ता, साथी गौतम

सेनगुप्ता, साथी असित पाण्डेय, साथी नईम खान आदि नेताओं ने माल्यार्पण किया।

गोविन्दपुर: पार्टी प्रखण्ड कमेटी की ओर से नेताजी चौक पर नेताजी सुभाष की प्रतिमा पर साथी विमल चन्द्र दे, विनोद वर्मन आदि नेताओं ने माल्यार्पण किया।

धनबाद : पार्टी की धनबाद जिला कमेटी की ओर से धनबाद में साथी शानू चौधरी, साथी मौ. सलाउद्दीन, साथी विशेश्वर प्रसाद, साथी प्रेम चन्द्र गुप्ता, साथी मानू चौधरी ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं नेताजी जन्मदिन को देशप्रेम दिवस के रूप में मनाया।

पाकुड़िया : पार्टी की प्रखण्ड इकाई की ओर से साथी स्टीफन मराण्डी ने नेताजी जन्मदिवस को देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आदिवासी युवकों द्वारा बाजा-गाजा से सुसज्जित होकर इस समारोह को शानदार ढंग से देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया।

जामताड़ा: पार्टी जिला इकाई की ओर से करमाटॉड़ में नेताजी जयन्ती देश प्रेम दिवस के रूप में मनायी गयी। इस अवसर पर जिलामहामंत्री साथी अरूण मंडल, लोलिन हेमरम, साथी भीम मण्डल, आदि नेताओं ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

गोड्डा: देश प्रेम दिवस के अवसर पर रौतारा चौक स्थित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्मारक पर न्यायिक व प्रशासनिक पदाधिकारियों, विभिन्न राजनैतिक संगठनों, स्वतंत्रता सेनानियों ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। स्मारक स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी ने देश प्रेम दिवस के अवसर पर कहा कि नेताजी ने आजादी की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वह देश के लिये मर मिटने के तैयार रहते थे। हमें उनके देश प्रेम और उनके संगठनात्मक कौशल से सीख लेनी चाहिये। इसके अलावा सर्वजीत झा अन्तेवासी ने रक्त से नेताजी का तिलक किया। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष देवेन्द्र सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह, अविधवक्ता दीनानाथ झा, कोर्ट के रजिस्टार एस.के. सिंह, दी न्यू आईडिल के छात्र देवेश कुमार, नीतू कुमारी, नमन कुमार, संत थामस के प्रियेश कुमार शुक्ला, सिदो-कान्हू के अमर कुमार तथा भारत-भारती के सुभम महारानी, लिपिका वत्स आदि भी उपस्थित थे।

बिहार

पटना : अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की बिहार राज्य कमिटी की ओर से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्मदिवस 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के राज्य कार्यालय रामकृष्ण नगर में पार्टी के प्रांतीय महासचिव साथी आजाद ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरूआत की। साथी आजाद ने नेताजी के सपनों का भारत बनाने के लिये साम्राज्यवादी शक्तियों को परास्त करने, जल-जंगल-जमीन के अधिकार की रक्षा करने के लिये समझौता विहीन संग्राम को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर साथी अशोक कुमार गुप्ता, अविनाश कुमार, पवन कुमार, श्रीनिवास सिंह, रामजी सिंह, नागेन्द्र प्रसाद राजीवन प्रसाद, कुमुद प्रसाद सिंह, आदिन नेताओं ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और नेताजी के कृतित्व पर प्रकाश डाला।

मुजफ्फरपुर : पार्टी की मुजफ्फरपुर जिला इकाई एवं अग्रगामी किसान सभा के संयुक्त तत्वावधान में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 113वीं जयन्ती देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर अग्रगामी किसान सभा के प्रदेश संयोजक साथी राजेश्वर पाण्डेय ने झण्डारोहण कर कार्यक्रम की शुरूआत की। इस अवसर पर नेताजी की प्रतिमा पर उपस्थित पार्टी नेताओं ने माल्यार्पण किया और एक आमसभा भी आयोजित की गयी। आमसभा में उपस्थित वक्ताओं ने नेताजी के वैज्ञानिक समाजवाद में आस्था व्यक्त करते हुये साम्राज्यवादी शक्तियों को परास्त करने का संकल्प लिया। देश प्रेम दिवस की यही पुकार, जल-जंगल-जमीन पर हो अपना अधिकार; भूखे बेरोजगारों का यही है अरमान, खाद्य सुरक्षा और रोजगार का हो मुकम्मल इंतजाम आदि नारों से सभा गुंजायमान हो गयी। नेताओं ने कहा कि भू-हद बंदी ही नहीं मनि हद मंदी कानून बनाने के लिये अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक पंचायत से राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन तेज करेगा। सभा को छात्र ब्लॉक एवं केन्द्रीय समिति सदस्य साथी अमरेश कुमार सिंह, साथी वकील ठाकुर, साथी हबीब अंसारी, साथी रामदयाल राम, साथी राकेश कुमार सिंह, साथी जयनन्दन सिंह, छात्र ब्लॉक दिल्ली इकाई के नवीन पंकज, भाकपा नेता सत्यदेव चौधरी, चन्देश्वर प्रसाद सिंह, विजय किशोर कुमार, चिन्ता देवी, शान्ती देवी, और वीना देवी ने सम्बोधित किया।

पूर्णिया : अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की जिला इकाई द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 114वीं जयन्ती देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष नंद कुमार सिंह तथा महासचिव चन्द्रशेखर मिश्र ने किया। आलोक कुमार सिंह उर्फ लाल बाबु आदि ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा कहा कि आज देश को नेताजी के विचारों की जरूरत है।

इसके अलावा बिहार के आरा, नवादा, शिवहर आदि जिलों में भी देश प्रेम दिवस मनाया गया।

हरियाणा

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की हरियाणा राज्य कमिटी की ओर से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्मदिवस 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया गया। प्रात: 10.30 बजे नेताजी की प्रतिमा पर पार्टी के राज्य अध्यक्ष साथी डी.के. शर्मा, अग्रगामी किसान सभा के नेता हरपाल सिंह, राज्य सचिव बलबीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष लजविन्दर सिंह, सचिव सतपाल शर्मा, साथी सुभाष अरोड़ा, करनाल जिला अध्यक्ष रविन्द्र शर्मा, महासचिव ललित सरदाना आदि नेताओं ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुये साथी डी.के. शर्मा ने कहा कि आज हमारा देश साम्राज्यवादी शक्तियों के दबाव में आ गया है, शिक्षा एवं कृषि सेवायें भी विदेशी कम्पनियों के हाथ में सौंप दी गयी

है। आकाश छूती महँगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। ऐसी परिस्थिति में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की विचारधारा पर चलकर ही हम देश को बचा सकते हैं। इसके लिये समझौता विहीन साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिये और नेताजी सपनों का भारत के पुनर्निर्माण के लिये देश वासियों को आगे आना होगा।

महाराष्ट्र

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की महाराष्ट्र राज्य कमिटी की ओर से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्मदिवस 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी की राज्य इकाई की ओर से नागपुर शहर तथा नागपुर जिला ग्रामीण की ओर से मानस चौक पर स्थित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा पर पार्टी की केन्द्रीय कमिटी के सदस्य साथी बलवन्त राय मेहता ने माल्यार्पण कर कार्यक्रम का आरम्भ किया। इस अवसर पर एक सभा का आयोजन किया गया। जिसे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साथी धर्मराज दुबे ने अध्यक्षता की। सभा में स्वतंत्रता सेनानी शंकर लाल लांजेवाल, रूईकर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष मुकुन्द मुले, गौतम बोस, भाकपा के नगर कमिटी सदस्य साथी संजय राउत, फारवर्ड ब्लॉक के नगर कमिटी अध्यक्ष डॉ. श्रीकान्त धोटे, नागपुर जिला ग्रामीण अध्यक्ष डॉ. धर्मराज राउत आदि ने अपने विचार रखे। सभा का संचालन करते हुये पार्टी के प्रदेश महासचिव साथी अरूण वांकर ने कहा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सारी सत्ता जनता के हाथ के अनुरूप सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिये छोटे राज्यों की जरूरत हैं और इसके लिये अलग विदर्भ राज्य का निर्माण गठन किया जाना चाहिए। समारोह में श्री गुणवन्त नागपुरे, जसवन्त चित्तले, कन्नू चौबे, स्वामी संजय कंटकंबार, दीपक वाघमरे, प्रवीण गभनेय, परशुराम राउत, भीमराव खोण्डे, मास्टर राउत, रामचन्द्र बाघमरे राज शलोटे आदि नेताओं ने अपने विचार रखे।

उत्तर प्रदेश

पीलीभीत : अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 114वीं जयन्ती देश प्रेम दिवस के रूप में मनायी गयी। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश महासचिव साथी शिव नारायण सिंह चौहान के नेतृत्व में नेताजी चेतना यात्रा निकाली गयी और वह जिले के विभिन्न जगहों में भ्रमण करते हुये नेताजी के विचारों को जन–जन तक पहुँचाने का काम किया। यात्रा गजरौला, पूरनपुर, घुंगचिहाई, बंडा, विलसंडा, विसलपुर तथा बरखेरा में जगह–जगह नुक्कखड़ सभाओं का आयोजन किया गया। इस यात्रा में नारायण लाल मौर्य, मनोज पाण्डेय, नंदकिशोर कश्यप, नितीन गुप्ता, विरेन्द्र पाण्डेय, सुभाष गंगवाल, विकास शर्मा, हरिओम यादव, अजित सिंह, नरेन्द्र सिंह, अखिलेश गंगवाल, खेमपाल मौर्य आदि नेतागाण शामिल थे। इस यात्रा के माध्यम से वक्ताओं ने देश गौरव नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के देश भक्ति पूर्ण जीवन चरित्र को के.जी. से पी. जी. तक पाठ्यक्रमों में शामिल करने की मांग उत्तर प्रदेश शासन से किया।

मध्य प्रदेश

हरदा : अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की मध्य प्रदेश कमेटी के तत्वावधान में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 114वीं जयन्ती देश प्रेम दिवस के रूप में मनायी गयी। उपस्थित नेताओं ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरूआत की। उपस्थिति जनसमुदाय को पार्टी राज्य अध्यक्ष साथी श्याम सुन्दर बिश्नोई के अतिरिक्त विरेन्द्र कुमार आनंद, पूर्व अध्यक्ष हरदा नगरपालिका, उमेश नायक, राम अवतार पवार, श्री चन्द्र गोपाल सोनी श्री वेद बिश्नोई, श्री राम बठिजा, श्री संदीप कुमार पंवार एडवोकेट श्री मोंहन सिंह सवनेर श्याम बाबु पंवार, प्रेम पवार, गफर खान रंगरेज, जाकिर भाई जीवराम, हेमराज जाट, रामजी पंवार, रामभरोस बिश्नाई (सरपंच), सुभाष गोदारा, संतोष सारण, चन्द्रशेखर बिश्नोई, मो. मुस्तफा, गब्बु भाई नारायण, आदि वक्ताओं ने नेताजी के बताये रास्ते पर चलने का संकल्प ग्रहण किया।

भोपाल: अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक और टी.यू.सी.सी की मध्य प्रदेश राज्य के संयुक्त तत्वावधान में देश गौरव नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयन्ती 23 जनवरी देश प्रेम दिवस के रूप में भोपाल में मनायी गयी। इस अवसर पर टी.यू.सी.सी. के राष्ट्रीय महासचिव साथी एस.पी. तिवारी, तथा पार्टी प्रदेश महासचिव साथी रामअवता पचौरी कार्यक्रारी अध्यक्ष सुरेश सिंह गौतम आदि नेताओं ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं दीप प्रज्जवलित कर नेताजी जयन्ती को देशप्रेम दिवस के रूप में हर्ष उल्लास के साथ मनाया।

इसके अलावा जिला सतना में पार्टी जिला इकाई द्वारा एडवोकेट राजेश शर्मा द्वारा नेताजी जयन्ती देश प्रेम दिवस के रूप में मनायी गयी। जिला कटनी में साथी संजय यादव, जिला देवास इकाई की ओर से साथी कैलाश डाबी, जिला रिवा इकाई में साथी सलमा सौदागर, जिला मंडला में निशा सिंह, जिला उमरिया में एडवोकेट अरूण गौतम, जिला उज्जैन में साथी जगदीश चावड़ा, अग्रगामी महिला समिती की नेत्री प्रेमलता चावड़ा, टी.यू.सी.सी. के प्रदेश अध्यक्ष साथी रामचन्द्र परमार, जिला संयोजक कमलेश परमार आदि ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया। नेताओं ने साम्राज्यवादी शक्तियों को परास्त करने तथा नेताजी समाजवादी भारत के पुनर्निर्माण के लिये संघर्ष को धारदार बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

उड़ीसा

देश गौरव नेताजी का 114वां जन्मदिवस मनाने के लिये अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के उड़ीसा राज्य कमिटी के कार्यकर्ताओं ने राज्य के कई क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन किया। सरतमान सिंह और संतोष मित्रा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भुवनेश्वर में नेताजी की प्रतिमा पर

माल्यार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा के पश्चात् नेताओं ने सरकार को 23 जनवरी को 'देश प्रेम दिवस' घोषित करने का आह्वान करते हुये ज्ञापन सौंपा और मांग किया कि नेताजी के इतिहास और बलिदान को विद्यालय और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिये। इसके अलावा विशेष कार्यक्रमों का आयोजन गंजम, बेहरामपुर, बालासोर, कटक और खुर्दा रोड़ जिलों में भी किया गया। साथी मिर सलामत अली, मनोरमा पाधी आदि ने भी जनसभा को संबोधित किया।

तमिलनाडु

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की तमिलनाडु राज्य कमेटी ने 'देश प्रेम दिवस' पर तमिल ढंग से एवं अपने परंपरागत तरीकों से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस अवसर पर चैन्नई में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव साथी देवब्रत बिश्वास मुख्य अतिथि थे। पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताजी के अनुयायियों ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया व श्रद्धासुमन अर्पण किया। एकत्रित भीड़ को संबोधित करते हुये साथी बिश्वास ने कहा कि केन्द्र सरकार नेताजी के जन्म दिवस को तुरन्त देश प्रेम दिवस घोषित करे। इसके अलावा उन्होंने यह भी मांग किया कि नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिये नेताजी का इतिहास केजी से लेकर पीजी के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिये। साथी पी.वी. कादिरवन और साथी वी.एस. नवामनि ने पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। इसके अलावा राज्य के विभिन्न जिलों जैसे मदुरै, डिंडीगुल, तिरूचि, विरूधु नगर, नेल्लाई आदि में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसे साथी पी.एस. जयरमन, साथी सुब्बुराज, साथी एस. थानीकोडि, साथी ए. जोसेफ सागायाराज, साथी कासिमायान और अन्य नेताओं ने संबोधित किया। आजाद हिन्द फौज के सिपाहियों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में मिठाईयाँ बांटी गई, कला और खेलों का आयोजन किया गया। तमिलनाडु राज्य में नेताजी के अनुयायियों और फारवर्ड ब्लॉक के कर्ताओं ने देश प्रेम दिवस एक त्यौहार के रूप में मनाया गया। विभिन्न स्थानों पर राज्य सरकार के मंत्रि, विधायक, सांसद और प्रशासनिक अधिकारियों ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

पाण्डिचेरी

पाण्डिचेरी में अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुराना बस स्टैण्ड के नजदीक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक राज्य कमिटी महासचिव साथी मुथु ने सर्व प्रथम माल्यार्पण किया और एकत्रित भीड़ को संबोधित किया। साथी वेंकटेश पेरूमल, राज्य कमिटी अध्यक्ष, साथी सुकुमार, मोहन, जयकुमार, रविचन्द्रन, रंगन आदि ने भी संबोधित किया। वर्ग संगठन के नेताओं ने भी एकत्रित भीड़ को संबोधित किया। ऑल इण्डिया यूथ लीग पाण्डिचेरी राज्य कमिटी ने 'देश प्रेम प्रेम दिवस' के अवसर पर रक्त-दान शिविर का आयोजन किया। जिसमें 40 नौजवान साथियों ने रक्त कोष में रक्त दान किया।

केरल

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केरल राज्य कमिटी ने 'देश प्रेम दिवस' के अवसर पर राज्य के सभी 14 जिलों में बड़ी धूम-धाम से मनाया गया। सभी स्थानों पर शपथ ग्रहण का भी आयोजन किया गया। तिरूवनंतपुरम में साथी वी. राम मोहन, राज्य महासचिव, ने राज्य विधानसभा के सामने स्थित नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और एकत्रित समूह को संबोधित किया। साथी अरूण सासि, साथी रजित राजेन्द्रन और साथी राजन अम्बुरी आदि ने भी एकत्रित भीड़ को संबोधित किया। अन्य जिलों में नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के उपरान्त नेताओं ने शपथ ग्रहण किया। साथी ताम्पी पुन्नाथला (कोल्लम), साथी कलातील विजयन (अलापुझा), साथी अब्दुल खादेर वझाकला (कोझिकोड), साथी सुदाकरण (व्यानाद), साथी राजन कूदाली (कन्नूर), साथी विजयन (कासरगोड), साथी वेल्लादुरै पाण्डियन (इदुकी), साथी सिवान (कोट्टायम), साथी एन. वेलप्पन नायर, साथी के.आर. ब्रह्मानंदन, साथी थंकचन वर्गीस और साथी हुमायुँ आदि नेताओं ने विभिन्न स्थानों पर जन समुह को संबोधित किया।

कर्नाटक

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक कर्नाटक राज्य इकाई ने टीयूसीसी के साथ संयुक्त रूप से कर्नाटक में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्मजयन्ती 'देश प्रेम दिवस' शानदार ढंग से मनाया। बेंगलौर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहाँ विधान सभा के सामने अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक और टीयूसीसी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राज्य के मुख्यमंत्री श्री येदुरप्पा ने भी नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। औरतों और बच्चों सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नेताजी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पण किया। श्री येदुरप्पा ने नेताजी के बलिदानों को बताते हुये नई पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। साथी जी. आर. शिवशंकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष टीयूसीसी और राष्ट्रीय सचिव फारवर्ड ब्लॉक ने 23 जनवरी को 'देश प्रेम दिवस' घोषित करने की मांग की। उन्होंने यह भी मांग किया की केन्द्र सरकार नेताजी के लापता होने से संबंधित मुखर्जी जाँच आयोग की रिपोर्ट स्वीकार करें। उन्होंने यह भी घोषणा किया कि अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक और टीयूसीसी आयोग की रिपोर्ट स्वीकार करने के लिये आन्दोलन करेगी और सरकार पर दबाव डालेगी। साथी सिद्धारमैया और साथी अम्रुतेश आदि अन्य नेताओं ने भी एकत्रित भीड़ को संबोधित किया।

आन्ध्र प्रदेश

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की सांगठनिक कमिटी ने 'देश प्रेम दिवस' राज्य के विभिन्न स्थानों पर मनाया। साथी मुरलीधर देशपाण्डे के नेतृत्व

में फारवर्ड ब्लॉक के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हैदाराबाद में आयोजित कार्यक्रम में नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके अलावा राज्य के विभिन्न स्थानों, तिरूपति, कुरनूल, मेडक, अदिलाबाद, रंगा रेड्डी, खम्मम आदि स्थानों पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई स्थानों पर जनसभा और सेमिनार का आयोजन किया गया। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्मदिवस को 'देश प्रेम दिवस' घोषित करने के लिये सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा। बशीरघाट प्रेस क्लब में एक सेमिनार का आयोजन किया गया तथा सिकन्दराबाद रेलवे स्टेशन पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

पंजाब

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक, नेताजी सुभाष क्रान्ति मंच और नेताजी मॉडल स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में पंजाब के रोपड़ में लड़कों और लड़कियों के लिये द्वितीय नेताजी सुभाष मेमोरियल ऑल इण्डिया हॉकी गोल्ड क्लब का आयोजन किया गया। जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगड़, और पंजाब से प्रतिभागी दलों में लड़कों की 12 तथा लड़कियों की 4 दलों ने भाग लिया। यह टुर्नामेन्ट चार दिनों तक चला। श्रीमती हरिन्दर कौर बरार, असिस्टेंट एक्साईस एवं टेक्सेशन कमीश्नर ने टुर्नामेंट का उद्घाटन किया और श्री एल.के. यादव, आईपीएस, एसएसपी रोपड़ ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विजेता दल को 5100/- रुपये और दूसरे स्थान वाले दल को 3100/- रुपये का पुरस्कार वितरित किया गया। इस आयोजन से नेताजी जन्मदिवस पर कई छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अन्त में नेताजी के सपनों का भारत बनाने का प्रस्ताव ग्रहण किया गया। नेताजी के जन्मदिवस पर शपथ लिया गया और इस प्रकार की देशभक्ति की भावना जगाने के लिये कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

उत्तराखण्ड

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की उत्तराखण्ड राज्य कमिटी ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के 114वें जन्म जयन्ती पर काशीपुर, बाजपुर, और हरिद्वार के कार्यक्रमों का आयोजन किया। साथी सुरेन्द्र कम्बोज, पीर बक्श, डॉ. दास, राजकुमार और प्रमोद शर्मा आदि ने विभिन्न स्थलों पर एकत्रित जन-समुह को संबोधित किया। नेताजी की प्रतिमा और फोटो पर माल्यार्पण किया गया और कई स्थानों पर बच्चों में मिठाईयाँ भी वितरित की गई। नेताओं ने अपने संबोधन में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के ऐतिहासिक जीवन और उनके बलिदानों को बताया।

जम्मु और कश्मीर

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की जम्मु और कश्मीर इकाई ने घाटी में कई स्थानों पर बर्फवारी के बावजूद भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर, बडगाम, बारामुला, हंदवाड़ा, गंडेरबल, जम्मु, कटुआ और राजौरी में नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथी राजेन पादरी, गुलाम मोईउद्दीन शेख, डॉ. खारू, मलिक नुरूल अमिन, शाहीद मंसूर, अमीर गिलानी, रिज गिलानी, जी.एम. मल्ला, अशरफ, विक्रम चंद, पी.एल. भट्ट आदि के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्रीनगर का दिल कहे जाने वाला लाल चौक के सामने नेताजी की फोटो पर जब सैकड़ों नौजवानों ने जय हिन्द का नारा लगाना आरम्भ किया तो श्रीनगर वासियों के लिये एक अलग भी अनुभव प्रतीत हुआ। बड़गाम में अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने स्कूली छात्रों और अन्य साधारण बच्चों में मिठाईयाँ बांटी।

पश्चिम बंगाल

नेताजी की 114वीं जन्मजयन्ती पश्चिम बंगाल में बड़े ही गर्मजोशी के साथ मनाया गया। नेताजी जन्म जयन्ती सिर्फ अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनता, क्लब एवं नौजवान और छात्रों के समूह ने भी बड़े उत्साह के साथ मनाया। नेताजी बंगाल के साथ-साथ पूरे भारत वर्ष के महान राष्ट्रीय हीरो है।

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोलकाता के रेड रोड़ पर नेताजी के पैरों तले 23 जनवरी 2010 को एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमेशा की तरह अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की नेताजी जयन्ती कमिटी और पश्चिम बंगाल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन किया गया। साथी सुब्रत बोस ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इसके अलावा कई नेताओं ने जन-समूह को संबोधित किया जिनमें साथी अशोक घोष, महासचिव अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक पश्चिम बंगाल राज्य कमिटी, बिमान बोस, अध्यक्ष वामफ्रंट पश्चिम बंगाल, साथी बुद्धदेव भट्टाचार्य, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल सरकार आदि के अलावा साथी मोतिलाल माइत्रा, महासचिव सेन्ट्रल नेताजी जयन्ती कमिटी आदि थे। साथी अशोक घोष ने अपने भाषण में कहा कि यह वर्ष बिल्कुल भिन्न है, इस वर्ष चारों वामपंथी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों ने संयुक्त रूप से हाथ मिलाकर सामुहिक पत्र डॉ. मनमोहन सिंह को संबोधित करते हुये 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस घोषित करने का आह्वान किया। आज गरीब और दलित भूख और बेरोजगारी से लाचार होने के कारण देशभक्ति की भावना को भूल गये है। जिसे सिर्फ नेताजी के जीवन और संघर्ष को याद करके ही जनता में देशभक्ति की भावना जागृत किया जा सकता है।

साथी बीमान बोस ने कहा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एकमात्र राष्ट्रीय हीरो हीरो थे जिन्होंने देश की आजादी और खुशहाली के लिये नेतृत्व किया।

साथी बुद्धदेव भट्टाचार्य ने अपने भाषण में खुलकर कहा कि कम्युनिस्ट नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के आकलन में गलत थे। उन्होंने आगे कहा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एक महान देशभक्त थे, उन्होंने जो भी किया सिर्फ और सिर्फ देश की आजादी और देश कल्याण के लिये किया।

वामपंथी पार्टियों का आह्वान: दिल्ली चलो – मार्च 12, 2010

वामपंथी पार्टियाँ : सी.पी.आई., सी.पी.आई.(एम.), अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक और आर.एस.पी. आपका 12 मार्च के दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित विशाल रैली में आने का आह्वाहन करती है कि आप 12 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली विशाल रैली में शामिल हों और केन्द्र सरकार की उन नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करें जो मूल्य वृद्धि के माध्यम से गरीबों के बजट को लूट रही है। यह रैली सभी लोगों को सस्ता राशन, काम और रोजगार मुहैया कराने तथा भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने की मांग के लिये किया जा रहा है।। इसके अलावा रैली का उद्देश्य बंगाल की वामपंथी कार्यकर्ताओं के खिलाफ तृणमूल–माओवादी हिंसा की घोर भर्त्सना करना भी है।

महँगाई के खिलाफ और सस्ते राशन के लिए

जरूरी खाद्य पदार्थों में अप्रत्याशित महँगाई का शिकार देशभर की जनता हुई है। इस महँगाई ने उनके रोजमर्रे की जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जिंदा रहने के लिये जो जरूरी है, जैसे चावल, आटा, दाल चीनी, खाद्य तेल, दूध, सब्जी आदि – ये सभी इतनी महँगी हो गई कि इन्हें खरीद पाना मुश्कि हो गया है। इस सबके लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार की नीतियाँ जिम्मेवार है। आम आदमी का नारा देते हुए कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन सरकार में आते ही उसने जिन नीतियों को अपनाया उससे सिर्फ खास आदमी को ही फायदा मिला।

उदाहरण के लिए:

- आयातित गेहूँ की खरीद के लिये उसने बड़े व्यापारियों को 12 से 14 रुपया दिया, जबकि उसी वर्ष भारतीय किसानों को मात्र 9.50 रुपया दिया गया।
- महँगे आयात के बावजूद राशन की दुकानों में गेहूँ के वितरण में लगातार कटौती जारी है।
- खुले बाजार में गेहूँ की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है।
- इससे किसे फायदा हो रहा है? न तो किसान और न ही आम उपभोक्ता, बल्कि इसका फायदा मात्र बड़ी कंपनियों को मिल रहा है।

यही कहानी चीनी के साथ भी है।

दो साल पहले जब किसानों ने गन्ने की बहुत ही बेहतर उपज पैदा की तो उन्हें उनके उत्पादन के लिये उचित मूल्य न देकर दंडित करने का काम किया गया।

इससे किसे फायदा मिला? बड़ी चीनी कंपनियों ने इससे बहुत अधित मुनाफा कमाया। 33 कंपनियों ने मात्र एक सामल में अपने मुनाफे को 30 करोड़ से बढ़ाकर 900 करोड़ कर लिया जो 2900 प्रतिशत होता है! किसान तो इससे प्रभावित हुआ ही और इसके साथ ही उपभोक्ता को भी एक किलो चीनी के लिए 40 रुपये देना पड़ा।

वायदा व्यापार के दायरे में खाद्य पदार्थों को शामिल करने की इजाजत देना – यह सरकार की एक अन्य नीति रही जिसके कारण बेतहाशा महँगाई बढ़ी। जरूरी खाद्य पदार्थों के लिये मुनाफाखोरी की इजाजत क्यों दी गई? वायदा कारोबार के लिये शुरूआत में गेहूँ पर जो रोक लगी थी, उस रोक को भी केन्द्र सरकार ने हटा लिया। प्राईवेट कंपनियों ने इस क्षेत्र में भी खूब मुनाफा कमाया। हम खाद्य पदार्थों के सभी वायदा करोबार पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते है।

केन्द्रीय सरकार ने लाखों को राशन–कार्ड से वंचित कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को असल में खत्म कर दिया है। ग्रामीण भारत में एक व्यस्क के लिये गरीबी रेखा की 11 रुपये प्रतिदिन की बोगस की परिभाषा का परिणाम यह हुआ कि गरीबों की एक बहुत बड़ी संख्या में बी.पी.एल. कार्ड नहीं मिले और बाकी गरीबों के बारे में कहा गया कि वे गरीबी की रेखा के ऊपर है। एक आदमी या औरत जिसकी कमाई 15 रुपये प्रतिदिन है, क्या वह गरीब नहीं है? उन्हें बी.पी.एल. कार्ड क्यों नहीं मिले? पिछले 5 वर्षों में विभिन्न राज्यों में राशन–प्रणाली के लिए जाने वाले चावल और गेहूँ में 75 प्रतिशत की कटौती केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई है।

हम मांग करते हैं कि असंगठित मजदूरों के सभी हिस्सों – जो व्यस्क कामगार जनता का लगभग 80 प्रतिशत हैं – को बी.पी.एल. कार्ड दिया जाए। हम मांग करते हैं कि तत्काल एक कानून बनाकर प्रत्येक परिवार को 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कम से कम 35 किलो अनाज दिया जाए।

सबके लिये रोजगार

वामपंथी पार्टियों ने एक बड़े संघर्ष के माध्यम से पिछली यू.पी.ए. सरकार को ग्रामीण भारत में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने का कानून बनाने पर मजबूर किया था। लेकिन इस कानून के तहत हर परिवार को केवल एक व्यक्ति को ही यह रोजगार मिल सकता है। इसके अलावा नरेगा (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून) में काम करने वालों को न्यूनतम वेतन मिलने की गारंटी नहीं है। पीस रेट वेतन (मात्रानुपाती दर) को उत्पादकता के बहुत ऊँचे और नामुमकिन मानदंडों से जोड़ा गया है, जिसके कारण देश के बड़े भाग में मजदूरों को पूरा वेतन नहीं मिलता। शहरी इलाकों को रोजगार गारंटी कानून से पूरी तरह बाहर रखा गया है। करोड़ों नौजवान और नवयुवतियाँ काम की तलाश में हैं। अत: सरकार द्वारा शहरी इलाकों में रोजगार गारंटी करने वाला कानून बनाना निहायत जरूरी हो गया है।

अभी तक सरकार ही रोजगार मुहैया कराने वाली सबसे बड़ी एजेन्सी रही है। मगर अपनी उदारवादी आर्थिक नीतियों के चलते केन्द्र सरकार ने भर्ती पर रोक लगा रखी है। इसका रोजगार पर तथा विशेषकर अनुसूचित जाजि/जनजातियों के युवाओं के लिये रोजगारकी उपलब्धता पर बहुत विपरीत असर पड़ा है। अल्पसंख्यक समुदायों को भी नौकरियों सं वंचित रखा गया है और केन्द्र सरकार उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिये कोई कदम नहीं उठा रही है। विकलांग नागरिक जिन्हें चिन्हित नौकरियों में 3 प्रतिशत के आरक्षण का हक मिला हुआ है को भी उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है।

हम मजदूरों की सुरक्षा की मांग करते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार नौकरियों में भर्ती पर लगे प्रतिबंध को हटायें, हम मांग करते हैं कि अनुसूचित जातियों/ जनजातियों तथा विकलांगों के लिये आरक्षित नौकरियों के रिक्त स्थानों को फौरन भरा जाए।

भूमि सुधार तथा भूमिहीनों व बेघरों के लिये जमीन के पट्टे

हमारे लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या गांवों में रहती है और उनमें भूमिहीन खेत-मजदूर शामिल है और ऐसे लोग भी है जिनके पास घर बनाने के लिये जमीन तक नहीं है। ऐसी स्थिति में भूमिसुधार के महत्व पर जोर देने की जरूरत है। जब तक हमारी ग्रामीण जनता के अधिकांश के पास कोई परिसम्पत्ति न हो और जब तक उनकी क्रय-क्षमता कम रहेगी, भारत का विकास कैसे हो सकता है? भूमिहीनों को जमीन देने पर जोर देने की बजाय केन्द्र की सरकारों ने लगातार इसके उलट नीतियाँ अपना री है। वे कार्पोरेट कम्पनियों को जमीन खरीदने की या छोटे किसानों से जमीन पट्टे पर लेने की इजाजत दे रही हैं। विभिन्न सरकारों द्वारा तथाकथित बंजर भूमि के विशाल इलाके कार्पोरेट कंपनियों को सौंपे जा रहे हैं।

भारत की लाखों जनता के पास रहने के लिये घर नहीं है। इन्दिरा आवा योजना एकदम नाकाफी है। जरूरत है एक उचित नीति की जो लोगों के आवास के लिये जमीन और मकान सुनिश्चित करे। इस पर तुर्रा यह कि केन्द्रीय सरकार अभी तक किसानों की जमीन की जबर्दस्ती अधिग्रहण करने के लिये 1894 के क्रूर और पुराने भूमि अधिग्रहण कानून का इस्तेमाल कर रही है। हम मांग करते हैं कि 1894 का कानून रद्द किया जाए, विस्थापन को न्यूनतम किया जाए और ऐसे कानून बनाये जाएं जिससे प्रभावित लोगों को पूरा हर्जाना मिल सके, लाभ में हिस्सा आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित हों।

पश्चिम बंगाल के साथ एकजुटता

आज पश्चिम बंगाल जो कि देश में वामपंथी और प्रगतिशील आन्दोलन का हृदय है, पर प्रतिक्रियावादी ताकतें भयंकर हमला कर रही हैं। ये ताकतें वामपंथी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों को खत्म करने के लिये उनके घरों पर हमला करने और उन्हें जलाने के लिए हिंसा का प्रयोग कर रही हैं, यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्श रही हैं। लोकसभा चुनावों के बाद से 168 वाममोर्चा नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की नृशंस हत्या की जा चुकी है। हमले का नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस माओवादियों के साथ मिलकर कर रही है। तृणमूल कांग्रेस और उसके नेतृत्व में चरम दक्षिणपंथी से चरम वामपंथी पार्टियों व ताकतों के गठबंधन का एकसूत्रीय कार्यक्रम है - पश्चिम बंगाल में अस्थिरता पैदा करना और इन हथकंडों के माध्यम से वाममोर्चा सरकार को सत्ता से बाहर करना।

पश्चिम बंगाल वामपंथी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोगों के लिये ही नहीं, बल्कि पूरे देश के जनवादी विचारों वाले नागरिकों के लिये चिन्ता का विषय है। हम तृणमूल-माओवादी हिंसा के खिलाफ पश्चिम बंगाल की जुझारू जनता के साथ जनवाद की रक्षा के लिये संघर्ष के साथ अपनी एकजुटता प्रकट करते हैं।

महँगाई पर रोक लगाओ, सबको सस्ता राशन दो

भूमिसुधार लागू करो, किसानों और आदिवासियों की जमीन की रक्षा करो

सबके लिये रोजगार मुहैया करो

पश्चिम बंगाल में वामपंथियों के खिलाफ हिंसा बंद करो।

राजनैतिक दबाव में संप्रग सरकार का अपने सहयोगी दलों के समक्ष हास्यापद समर्पण

22 फरवरी 2010 को संसद की संयुक्त सत्र में होन वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण से पूर्व समाचारपत्रों के अनुसार 18 फरवरी 2010 को रेलवे मंत्री ममता बैनर्जी ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल पर राष्ट्रपति के तैयार अभिभाषण में से सिलदा, पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल के ईएफआर कैम्प पर 15 फरवरी 2010 को माओवादियों के आक्रमण में 24 जवानों के मारे जाने और अनेक जवानों के घायल होने की घटना की निन्दा को अभिभाषण में से हटा लेने के लिये दबाव बनाया था। जब 22 फरवरी 2010 को राष्ट्रपति महोदया का संबोधन प्रारंभ हुआ तो यह सिद्ध हो गया कि प्रारंभ में प्रचारित समाचार सही था। यह घटना केन्द्रीय मंत्रिमंडल और रेलमंत्री के लिये सबसे अधिक शर्मनाक घटना है। मनमोहन सिंह सरकार अपने सहयोगी तृणमूल नेता ममता बैनर्जी की अनुचित मांगों का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाते है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में उसका लाभ लेना चाहते है। यह बहुत ही शर्म की बात है कि आतंक के मुद्दे पर अपना पक्ष सरकार ने कमजोर कर दिया और वह अपने सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बैनर्जी के आक्रामक दबाव के कारण झुक गई। इस बारे में सुश्री बैनर्जी का रिकार्ड बराबर मात्रा में दोषी और शर्मनाक है।

क्योंकि 24 जवानों की माओवादियों के कारण हुई हत्या के जघन्य कृत्य की निंदा करने से बचती रही है। क्योंकि उनके साथ उनकी गुप्त समझदारी है।

हाल ही में घटित महाराष्ट्र के पुणे में आतंकवादी घटना में पीड़ित परिवारों के परिजनों को राष्ट्रपति महोदया ने हार्दिक संवेदना अपने उक्त भाषण में व्यक्त किया, परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने सिलदा में हुये माओवादी आक्रमण जिसमें 24 जवान शहीद हो गये थे, उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मौन रह गयी। अपने भाषण में इस घटना को महत्व न देते हुये एक सामान्य वाक्य प्रयोग किया, जैसे कि वामपंथी अतिवादियों की हाल में विवेकहीन आतंक फैलाने की घटनायें जारी है, जिसमें बहुत सी निर्दोष लोगों की जा चली गई है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार पूणे की घटना का जिक्र करती है परन्तु सिलदा की घटनाओं को नहीं। सरकार के इस कृत्य से जवानों का मनोबल गिरता है तथा इस तरह संप्रग सरकार और तृणमूल नेता ममता बैनर्जी पूरे देश के सामने गुनहगार है। यही नहीं ऐसा करके देश में कानून व्यवस्था की प्रक्रिया को और ज्यादा कमजोर इन्होंने किया है, अपना राजनैतिक चरित्र उद्घाटित किया है। तृणमूल नेता अक्सर केन्द्रीय मंत्रिमंडलों की बैठक में माओवादियों के समर्थन में वकालत करती नहीं हिचकती है क्योंकि उन्हें पश्चिम बंगाल में चल रहे वाम शासन की फजीहत कराने की मंशा रहती है। यदि भारत सरकार ऐसी घटनाओं के घटित होने के बाद तृणमूल जैसी सहयोगी दलों के संकीर्ण राजनैतिक लाभ के दबाव में आकर माओवादी हिंसा के संदर्भ में अपना पक्ष कमजोर करती है तो वह माओवादी हिंसा को रोकने के अपने पूर्व के पक्ष का स्वत: हास्यापद तरीके से विरोध करती है। तृणमूल और कांग्रेस के गठजोड़ में पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने के प्रयास में, बनने वाला यह गठजोड़ एक नापाक गठजोड़ बनकर रह जायेगा और इस बारे में अंतिम निर्णय जनता ही देगी।

संप्रग सरकार बढ़ती कीमतों को रोकने में बुरी तरह असफल

डॉ. बरूण मुखर्जी

विगत दो वर्षों से मूलभूत सामग्रियों की कीमतें लगातार बढ़ रही है और केन्द्र सरकार मूक दर्शक बनी हुयी है और करोड़ों आम आदमी का जीवन दुभर हो गया है। अभी हाल में भारत के राष्ट्रपति महोदया ने 22 फरवरी 2010 के संसद के संयुक्त सत्र के अभिभाषण में कहा कि "खाद्यान्नों और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अनचाहा दबाव पड़ रहा है", जब मुद्रा स्फीति की दर खाद्य वस्तुओं के संदर्भ में 20 तक पहुँच चुकी है तो ऐसा नरम बयान देकर सरकार कीमतों के बढ़ने से उत्पन्न हुई विषम परिस्थिति को हल्के में ले रही हैं। सरकार बढ़ती कीमतों का कारण घरेलू उत्पादन में आई कमी और चावल, खाद्य तेल, और अन्य खाद्यान्नों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में चल रही वृद्धि को कारण बताया। यदी यही सत्य है तो इसका निदान क्या है ?अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसका कोई ईलाज नहीं है और बढ़ती कीमतें स्वभाविक है। क्या सरकार के इस रवैये से आम आदमी भूख से मरने के लिये बाध्य है ?इसका उत्तर कुछ और है जब कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश अपर्याप्त है, जब हजारों किसान आत्हत्या करने को बाध्य है, जब उत्पादन में कमी आने से तुरन्त आयात करने की उचित नीति नहीं है, जब जमाखोरों के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाये जाने है, जब खाद्य वस्तुओं के क्षेत्र में वायदा कारोबार पर कोई लगाम नहीं है तो खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ना स्वभाविक है। दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु भी ध्यान देने योग्य है। जब खाद्य वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही है वहीं सुख सुविधा पहुँचाने वाले सामान, मोटर गाड़ियाँ आदि की कीमतें उस तरह नहीं बढ़ रही है इसकी व्यापक समीक्षा होनी चाहिये।

इस संदर्भ में जो मूल तथ्य है कि सरकार के सुधारवादी कार्यक्रम मुद्रा स्फीति को बढ़ा रहे हैं। संप्रग सरकार की ताजा संशोधिल उर्वरक नीति निश्चित रूप से खाद्यान्नों की कीमतों को बढ़ाने के लिये जिम्मेवार होंगी। सुधारवादी कार्यक्रमों के अंतर्गत संप्रग सरकार उर्वरक की कीमत में वृद्धि कर रही है और रियायत की दरें कम कर रही है जो गरीब किसानों के हितों को गहरे आघात पहुँचा रही है। यही नहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि बजट प्रस्तुत करने के तुरन्त बाद पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढेंगी और इस तरह मूलभूत वस्तुओं की कीमतें एकबार और बढेंगी। जब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक नहीं किया जायेगा और उसे सुचारू नहीं बनाया जायेगा और खाद्य वस्तुओं को सस्ते दरों पर वितरित नहीं किया जायेगा इस समस्या से आम आदमी को राहत नहीं मिलेगी। यह समस्या बढ़ती बेरोजगारी से और भी गंभीर हो गयी है। एक तरफ बढ़ती कीमतों का दबाव और दूसरी तरफ बेरोजगारी जिसमें बड़े स्तर पर होने वाली छंटनी भी है से आम आदमी की तकलीफें बेहद बढ़ गई हैं वहीं ऐसे समय कारपोरेट घराने खूब मुनाफा कमा रहे हैं, धनी और धनी होते जा रहे है जबकि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिये आम आदमी को एकजुट होकर संप्रग सरकार की विध्वंसकारी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कमर कस लेना चाहिये। इन्हीं लक्ष्यों को सोचकर वाम दलों ने संयुक्त रूप से 12 मार्च 2010 को दिल्ली में विशाल रैली का आह्वान किया है। इस तरह संप्रग सरकार की जन-विरोधी नीतियाँ, बढ़ती कीमतों का विरोध, बेरोजगारी और छंटनी का विरोध और आम आदमी के लिये खाद्य सुरक्षा की गारंटी जैसे मुद्दों पर संप्रग सरकार को घेरने और उसके विरुद्ध संघर्ष शुरू करने का ऐलान किया है।

कोलकाता (नेताजी भवन) से ढाका (बंगबंधु भवन) तक ऐतिहासिक भ्रातृत्व यात्रा

भारत-बांग्लादेश-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम (बीबीपीपीएफ) के नेतृत्व में, 19 फरवरी 2010 से 22 फरवरी 2010 तक एक ऐतिहास भातृत्व यात्रा का आयोजन हुआ जो कोलकाता के नेताजी भवन से प्रारंभ हुई और ढाका के बंगबंधु भवन (एस.के. मुजिबुर रहमान भवन) तक पहुँची। नेताजी और मुजिबुर दोनों ही राष्ट्रीय नेता है, जिन्होंने साम्राज्यवाद और साम्प्रदायिकता के विरुद्ध बहादुरी पूर्वक संघर्ष किया। यह उचित समय है कि हमलोग साम्राज्यवाद और साम्प्रदायवाद के विरुद्ध उनके छेड़े संघर्ष से प्रेरणा लेकर इस संघर्ष को तेज करें ऐसा तभी संभव है जब हम सतर्क होकर नेताजी और मुजिबुर के दिखाये मार्ग पर चले। भारत-बांग्लादेश-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम (बीबीपीपीएफ) ने इस यात्रा का आयोजन साम्राज्यवाद और उसके स्थानीय एजेंटों के विरुद्ध संघर्ष को छेड़ने के लिये इन देशों की जनता को संघटित करने के लक्ष्य से किया था।

ढाका पहुँचने के साथ लोगों ने इस विशाल कार्यक्रम में भाग लिया और 21 फरवरी 2010 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया।

भारत-बांग्लादेश-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम (बीबीपीपीएफ) के सैकड़ों कार्यकर्ता जो विभिन्न राज्यों जैसे - उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, पुणे, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल से आये और इस ऐतिहासिक यात्रा में भागीदार बने 18 फरवरी 2010 नेताजी भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुये साथी देवब्रत बिश्वास, अध्यक्ष भारत-बांग्लादेश-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम (बीबीपीपीएफ) ने यात्रियों का अभिवादन किया और इस महान लक्ष्य की सफलता के लिये शुभकामनायें दी। साथी डॉ. बरूण मुखर्जी, सांसद, साथी मणिक समाजदार, सचिव भारत-बांग्लादेश-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम (बीबीपीपीएफ), साथी पार्थव बोस और अन्य साथियों ने संबोधित किया।

शहीदी दिवस 23 मार्च पर यूथ लीग का देश भर में धरना प्रदर्शन और कोर्ट अरेस्ट

ऑल इण्डिया यूथ लीग केन्द्रीय कमिटी की बैठक दिनांक 9 व 10 फरवरी 2010 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई। माननीय श्रीयुत् देवब्रत बिश्वास, पूर्व सांसद एवं महासचिव ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लॉक की उपस्थिति में तथा साथी मोईनुद्दीन शम्स, अध्यक्ष ऑल इण्डिया यूथ लीग की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में महान वामपंथी नेता का. ज्योति बसु को एक मिनट की मौन रखकर श्रद्धांजली दी गयी।

बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि ऑल इण्डिया यूथ लीग की अगला 21वां राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 20, 21 व 22 नवम्बर 2010 को झारखण्ड के धनबाद में होगी। जिसके तहत राज्य सम्मेलन सितम्बर और अक्टूबर 2010 तक पूरा किया जायेगा तथा जिला सम्मेलन जुलाई और अगस्त 2010 तक पूरा किया जायेगा।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि अगला केन्द्रीय कमेटी की बैठक 17 और 18 अप्रैल 2010 को धनबाद में होगी। ऑल इण्डिया यूथ लीग की 21वां राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी के लिये एक 'स्वागत समिति' का गठन दिनांक 18 अप्रैल 2010 को झारखण्ड इकाई की एक्सटेण्डेड कमेटी की बैठक में कि जाएगी।

23 मार्च 2010 को शहीद-ए-आजम भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरू की शहादत दिवस पर ऑल इण्डिया यूथ लीग के तरफ से 'सबको शिक्षा, सबको काम, सबको अच्छी चिकित्सा की मांग' को लेकर राज्यव्यापी मुख्यालयों पर धरना, प्रदर्शन व गिरफ्तारी दिये जाने का कार्यक्रम लेना होगा।

सभी राज्य में राज्य इकाई कि एक बैठक तथा कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा जिसके लिए निम्नलिखित तिथियों में निम्न साथियों को उपस्थित होने की जिम्मेदारी तय की गयी है:-

उत्तर प्रदेश	बरैली	21 फरवरी 2010
बिहार	पटना	22 फरवरी 2010
उत्तराखण्ड	हरिद्वार	26 फरवरी 2010
त्रिपुरा	अगरतला	27 फरवरी 2010

कर्नाटक बेंगलौर 27 फरवरी 2010
तमिलनाडु 28 फरवरी 2010
झारखण्ड धनबाद 2 मार्च 2010
मध्य प्रदेश भोपाल 2 मार्च 2010
आसाम गुवाहाटी 3 मार्च 2010
जम्मू एवं कश्मीर जम्मू 3 मार्च 2010
पंजाब रूप नगर 4 मार्च 2010
हरियाणा 5 मार्च 2010
दिल्ली दिल्ली 7 मार्च 2010
पाण्डीचेरी 7 मार्च 2010
उड़ीसा 10 मार्च 2010
केरल कोड़ी कोड 20 मार्च 2010

इसके अलावा यूथ लीग बेतहाशा बढ़ती हुई महँगाई पर रोक, बेरोजगारों को रोजगार दिलाये जाने की मांग लेकर चार वामपंथी दलों के दिल्ली के आह्वान पर 12 मार्च को आयोजित दिल्ली चलो रैली में ऑल इण्डिया यूथ लीग बढ़चढ़ कर भागीदारी करेगी।

किसान सभा का किसान बचाओ - देश बचाओ अभियान

अखिल हिन्द अग्रगामी किसान सभा की केन्द्रीय सचिव मण्डल की बैठक नई दिल्ली में 14 फरवरी 2010 को हुई। जिसकी अध्यक्षता साथी (डॉ.) हरीश गुप्ता, किसान सभा अध्यक्ष, ने की। सभा ने निर्णय लिया कि अप्रैल 2010 माह के दौरान अग्रगामी किसान सभा देश भर में जेल भरो आन्दोलन करेगी।

यह भी निर्णय लिया गया कि मार्च माह तक में राज्यवार विस्तारित बैठकें की जायेंगी और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिये जमीनी स्तर पर क्षेत्रीय और राज्यों के मुद्दों को चिन्हित करके अग्रगामी किसान सभा कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

जिन राज्यों के कार्यक्रम तय किये जा चुके हैं वे इस प्रकार है:

उत्तराखण्ड बाजपुर 26 फरवरी
मध्य प्रदेश भोपाल 4 मार्च
उत्तर प्रदेश सम्भल 6 मार्च
उत्तर प्रदेश बाराबंकी 7 मार्च
बिहार मुजफ्फरपुर 19 मार्च
झारखण्ड धनबाद 20 मार्च
उत्तर प्रदेश कानपुर 21 मार्च
तमिलनाडु 28 मार्च
त्रिपुरा अगरतला 3 अप्रैल
आसाम 4-5 अप्रैल

अखिल हिन्द अग्रगामी किसान सभा का राष्ट्रीय सम्मेलन दिसम्बर 2010 के प्रथम सप्ताह में बिहार में आयोजित किया जायेगा।

अखिल हिन्द अग्रगामी किसान सभा के सम्मेलनों के लिये निम्न प्रकार से अनुसूची तैयार की गयी है:

ग्राम पंचायत जून और जुलाई माह
ब्लॉक/तालुका/क्षेत्रिय अगस्त माह
जिला सम्मेलन सितम्बर-अक्तूबर माह
राज्य सम्मेलन नवम्बर माह

टीयूसीसी ने साप्ताहिक विरोध दिवस मनाया

सरकार की श्रमिक विरोधी और जनविरोधी नीतियों के तहत तथा असंगठित मजदूरों और गरीब श्रमिकों को उत्साहित करने और संघर्ष के लिये मजबूत करने के लिये टीयूसीसी सहित देश के 9 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनें 5 मार्च 2010 को संसद के सामने सत्याग्रह/धरना का प्रदर्शन कर रही है। इसी कार्यक्रम के तहत टीयूसीसी 15 फरवरी 2010 से 22 मार्च तक देशभर में साप्ताहिक विरोध दिवस मनाया।

16 फरवरी 2010 को बिहार में सैकड़ों रिक्शा चालकों और ट्रांसपोर्टरों ने जिला मजिस्ट्रेट नवादा के समक्ष प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम का आरम्भ प्रात: 11.30 बजे हुआ देर शाम तक चलता रहा। जिसमें टीयूसीसी के राष्ट्रीय महासचिव साथी एस.पी. तिवारी, साथी वकील ठाकुर, साथी अनिल शर्मा, साथी सत्येन्द्र सिंह और अन्य साथियों ने धरने को सम्बोधित किया। इसके अलावा 19 फरवरी 2010 को निर्माण मजदूर, बीड़ी कामगारों आदि ने मुजफ्फरपुर में विशाल प्रदर्शन किया। जिसका संचालन साथी हबीब अंसारी ने किया तथा जनसमूह को साथी एस.पी. तिवारी, वकील ठाकुर आदि ने किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

झारखण्ड के माईका इण्डस्ट्री में साथी सोमनाथ मुखर्जी और साथी बसन्ता तांतिल ने दैनिक मजदूरों, असंगठित मजदूरों के हक के लिये गिरिडीह की गलियों में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकाला, जिसमें फूटपाथ दूकानदारों, ठेला चालकों आदि ने भी हिस्सा लिया तथा जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। जिसे जिला मजिस्ट्रेट ने 15 दिनों में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

उत्तर प्रदेश में 17 फरवरी 2010 को मिर्जापुर में नरेगा में हो रही धांधलियों के विरोध में साथी हंसराज अकेला, साथी शम्सुद्दीन मंसूरी, साथी नारायण सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तथा प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सम्मेलन को साथी एस.पी. तिवारी ने संबोधित किया।

22 फरवरी 2010 को दिल्ली भवन व अन्य निर्माण मजदूर असंगठित मजदूर संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने संसद भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया, जिसका संचालन साथी पी.एन. द्वीवेदी, साथी एच.आर. तिवारी, साथी राज लक्ष्मी आदि ने किया। रैली को मुख्य रूप से साथी जी. देवराजन, साथी धमेन्द्र वर्मा, साथी डी.एन. झा आदि ने किया।